



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2019/भाद्र 21, 1941

No. 280]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2019/BHADRA 21, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

(जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

**विषय : टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास चाहे वह कोट किया गया हो अथवा कोट न किया गया हो का मलेशिया से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।**

**फा. सं. 6/13/2019-डीजीटीआर.**—मैसर्स गुजरात बोरोशिल लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष अधिकतम 4.2 मिमी. (0.2 मिमी. की सहन शक्ति सहित) मोटाई वाली कम से कम 90.5 प्रतिशत पारेषण के साथ टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास और जहां कम से कम एक डाईमेंसन 1500 मिमी. से अधिक हो चाहे उसे कोट किया गया हो अथवा कोट न किया गया हो” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया हो) का मलेशिया “जिसे आगे संबद्ध देश के रूप में भी कहा गया हो” से आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

## सब्सिडीकरण का आरोप

1. याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों / निर्यातकों को विभिन्न प्रांतों की सरकार और नगरपालिकाओं जिसमें उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य सार्वजनिक निकायों सहित संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ मिला है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक डोमेन में यथा उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों और संगत सरकारी एजेंसियों और लोक निकायों की अधिसूचनाओं और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों जिन्होंने ऐसी स्कीमों की विस्तृत जांच की है और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी निर्धारित की है, पर भरोसा किया है।

**परामर्श**

2. एएससीएम के अनुच्छेद 13 के अनुसार नई दिल्ली में मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 29 अगस्त, 2019 को जांच शुरूआत से पूर्व परामर्श किया गया था। मलेशिया सरकार के प्रतिनिधियों की टिप्पणियों को रिकार्ड में लिया गया है।

**सब्सिडी कार्यक्रम**

3. आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य से पता चलता है कि मलेशिया में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध मलेशिया की सरकार और /या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त नीचे यथा सूचीबद्ध अनेक सब्सिडियों से लाभ मिला है। कथित सब्सिडियों में निधियों का सीधे हस्तांतरण या निधियों अथवा देयताओं का संभावित सीधे हस्तांतरण; सरकार का राजस्व जो अन्यथा बकाया था, जिसे छोड़ दिया या संग्रहित नहीं किया गया; पर्याप्त मूल्य से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं।

**I. अनुदान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम**

1. प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी
2. बाजार विकास अनुदान

**II. कर प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

3. पायोनियर स्थिति
4. निवेश कर भत्ता
5. बढ़ा हुआ पूंजी भत्ता
6. मलेशिया के प्रांत का संवर्धन करने के लिए दोहरी कटौती
7. आयात शुल्क, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क पर ड्रा बैक
8. बिक्री कर से छूट
9. निर्माण क्रियाकलापों की आऊटसोर्सिंग करने के लिए आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
10. कल पूर्ण और उपभोग्य वस्तुओं पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
11. मशीनरी और उपस्कर पर आयात शुल्क और बिक्री कर से छूट
12. कच्चे माल/संघटकों पर आयात शुल्क से छूट
13. निर्यात का संवर्धन करने के लिए दोहरी कटौती
14. निर्यात कार्गो का संवर्धन करने के लिए दोहरी कटौती
15. बड़े हुए आयात के लिए भत्ता
16. प्रशुल्क से संबंधित प्रोत्साहन
17. संयंत्र और मशीनरी के लिए भत्ता

**III. निर्यात क्रेडिट और निर्यात वित्त पोषण के रूप में अभिज्ञात योजनाएं**

18. निर्यात क्रेडिट पुनः वित्त पोषण
19. क्रेता क्रेडिट गारंटी

4. यह आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त योजनाएं सब्सिडी हैं क्योंकि उनमें सार्वजनिक निकायों सहित ऐसे अलग-अलग देशों की स्थानीय सरकारों अथवा अन्य क्षेत्रीय सरकारों अथवा अलग-अलग संबद्ध देशों की सरकारों से वित्तीय अंशदान शामिल है और वह प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान करता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि वे कुछ उपक्रमों अथवा उपक्रमों के समूहों और /अथवा उत्पादों और/अथवा क्षेत्रों तक सीमित हैं और इस कारण से वे विशिष्ट और प्रतिसंतुलनकारणीय हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में वे आयात किए गए वस्तुएं पर घरेलू वस्तुओं का उपयोग पर निर्भर हैं और/अथवा निर्यात कार्य निष्पादन पर निर्भर हैं।

5. उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी अन्य सब्सिडी योजना जिसका लाभ उनके द्वारा उठाया गया है के संबद्ध में सूचना उपलब्ध कराएं। निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडी जो मौजूद रहा होगा और जिसका लाभ जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा उठाया गया होगा, की जांच करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं।

### क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

6. याचिकाकर्ता ने इस नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित घरेलू उद्योग को “क्षति” के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर सूचना प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबंध देश से कथित सब्सिडी युक्त आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

### जांच की शुरुआत

7. प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबंध देशों में संबंध वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात पर प्रति संतुलनकारी सब्सिडी के होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है और इस प्रकार के सब्सिडी युक्त आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसके अलावा उनकी मात्रा और कीमत के प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का घतरा है।

8. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी इसके माध्यम से कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 के संबंध में कथित सब्सिडी और परिणामी वास्तविक क्षति और घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे की जांच शुरू करते हैं।

### घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन मैसर्स गुजरात बोरोसिल लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उद्योग के शुरू में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वे भारत में संबंध वस्तुओं के एक मात्र उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अथवा संबंध देश से इसके संबंधित पक्षकारों में से किसी पक्षकार के द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता भारत में विचाराधीन उत्पाद का समग्र उत्पादन (100 प्रतिशत) करते हैं अतः याचिकाकर्ता इस नियमावली के अर्थ के अनुसार स्थिति को पूरा करते हैं और यह घरेलू उद्योग है।

### विचाराधीन उत्पाद

10. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई अधिकतम 4.2 मिमी. है (0.2 मिमी. की सहन शक्ति सहित ) और उसका न्यूनतम पारेषण 90.5 प्रतिशत है और जहां कम से कम एक डायमेसन 1500 मिमी. से अधिक है चाहें वह कोट किया हो अथवा न किया गया हो” (जिसे आगे “संबंध वस्तुओं” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” के रूप में भी कहा गया है)। संबंध वस्तु में अपेक्षित पारेषण का न्यूनतम स्तर लौह अवयव कम विशेष कर 200 पीपीएम से कम पर रख कर प्राप्त किया जा सकता है। पारेषण स्तर उस स्थिति में लगभग 2 प्रतिशत-3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है जब उसे एनटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तरल पदार्थ से कोट किया जाता है। ग्लास चाहे उसे कोट किया गया हो अथवा नहीं टेम्परिंग भट्टी में टेम्पर्ड / कठोर बनाया जाता है क्योंकि यह सौर अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। बाजार की बातचीत में इस उत्पाद को विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, लौ आयरन सौलर ग्लास, उच्च पारेषण फोटो वोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न वाला सौलर ग्लास आदि से भी जाना जाता है।

11. संबंध वस्तु का उपयोग सौलर फोटो वोल्टिक पैनलों और सौलर तापीय अनुप्रयोगों में एक संघटक के शुरू में किया जाता है। 3.2 मिमी. और 4 मिमी. की मोटाई के ग्लास का आमतौर पर प्रयोग चालू प्रवृत्ति के अनुसार सौलर फोटो वोल्टिक पैनलों और सौलर तापीय अनुप्रयोगों में किया जाता है। संबंध वस्तु का वर्गीकरण अध्याय शीर्षक 70071900 के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि इन संबंध वस्तुओं का आयात भी विभिन्न अन्य प्रशुल्क शीर्षा जैसे 70031990, 70051010, 70051090, 70052990, 70053090, 70071900 आदि के अंतर्गत किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक है और इस उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू रहेगा।

12. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा नीचे दिए गए अनुसार है: -

“टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास है जिसकी मोटाई अधिकतम 4.2 मिमी. है (0.2 मिमी. की सहन शक्ति सहित ) और उसका न्यूनतम पारेषण 90.5 प्रतिशत है और जहां कम से कम एक डायमेसन 1500 मिमी. से अधिक है चाहें वह कोट किया हो अथवा न किया गया हो”

### समान वस्तु

13. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबंध वस्तु और संबंध देश से आयात किया गया संबंध वस्तु समान वस्तु है। संबंध देश से निर्यात किए गए और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबंध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास और संबंध देश से आयात किया गया है

टेक्सचर्ड टफ़न्ड (टेम्पर्ड) ग्लास की तुलना आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे वस्तुओं की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विविधता, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में की जा सकती है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। यह दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इस कारण से उन्हें इस नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए। इस कारण से वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबंधित वस्तुओं को संबंधित देश से आयात किए जा रहे संबंधित वस्तुओं का “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

### **शामिल देश**

14. वर्तमान जांच मलेशिया में विचाराधीन उत्पाद को कथित सब्सिडी दिए जाने के संबंध में है।

### **जांच अवधि (पीओआई)**

15. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 (12 महीने) की है। हालांकि, क्षति जांच अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2015 से मार्च 2016, अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और जांच अवधि के आंकड़े शामिल हैं।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

16. संबंधित देश में निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, भारत में आयातकों और उपभोक्ताओं जिन्हें संबंधित माना गया है और घरेलू उद्योग को निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:

**महानिदेशक  
व्यापार उपचार महानिदेशालय  
वाणिज्य विभाग,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से जांच से संबंधित अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। प्राधिकारी के समक्ष के किसी गोपनीय अनुरोध करने वाला कोई पक्षकार यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को उपलब्ध सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।

### **समय-सीमा**

18. वर्तमान जांच संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामलों में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) की सूचना दें और अपने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और घरेलू उद्योग के आवेदन के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी में अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. प्रश्नावली का उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (प्रशिष्ट / उससे संबंध अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे यदि उसके किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा करते हैं तब दो अलग अलग सेट में उसे प्रस्तुत करें।

21. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से चिह्नित न किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी के पास यह स्वतंत्रता होगी कि वे ऐसे अनुरोधों की जांच करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों

को अनुमति दें। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के साथ-साथ प्रत्येक के दो (2) सेट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

22. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगे जो गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना की प्रकृति के हैं जो इस प्रकार की सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है यह सूचना जिसे गोपनीय प्रकृति के रूप में दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिस पर गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, सूचना का आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह इस प्रकार की सूचना क्यों नहीं प्रकट किया जाता सकता है कि संबंध में दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएँ।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई (यदि अनुसूची बनाना संभव न हो) और सारांशकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

26. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता के लिए आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना इसे किसी पक्षकार को प्रकट नहीं कर सकते हैं।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

27. नियम 7(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अथवा सूचना के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, 12th September, 2019

**Subject : Initiation of Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Textured Tempered Glass whether Coated or Uncoated from Malaysia**

**F. No. 6/13/2019-DGTR.**—M/s Gujarat Borosil Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of injury) Rules as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Countervailing on imports of "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm

(including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from Malaysia (hereinafter also referred to as the subject country).

### **Allegation of Subsidization**

1. The petitioner has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided at various levels by the Government of the subject country, including the government of different provinces and Municipalities in which producers/exporters are located, and other 'Public bodies'. The petitioner has relied upon the relevant Laws, Rules and Regulations and other Notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating Authorities who had conducted comprehensive investigation of such schemes and concluded existence of countervailable subsidy programs.

### **Consultation**

2. In terms of Article 13 of ASCM pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of Malaysia on 29<sup>th</sup> August 2019 in New Delhi. The comments of representatives of the Government of Malaysia have been taken on record.

### **Subsidy programs**

3. The prima facie evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in Malaysia have benefited from a number of subsidies granted by the Government of Malaysia and/or other public bodies as listed below. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds and potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; Provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

#### **I. Schemes Identified as Grants**

1. Subsidies on Natural Gas
2. The Market Development grant

#### **II. Schemes Identified as Tax Incentive**

3. Pioneer Status
4. Investment Tax Allowance
5. Accelerated Capital Allowance
6. Double deduction for promotion of Malaysian brand
7. Draw back on Import duty, Sales tax and Excise duty
8. Sales Tax Exemption
9. Exemption from Import Duty and Sales Tax for Outsourcing Manufacturing Activities.
10. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Spares and Consumables
11. Exemption from Import Duty and Sales Tax on Machinery and Equipment
12. Exemption from Import Duty on Raw Materials/Components
13. Double Deduction for Promotion of Exports
14. Double Deduction for Promotion of Export Cargo
15. Allowance for Increased Export
16. Tariff Related Incentive
17. Allowance for plants and Machinery

#### **III. Schemes Identified as Export Credit and Export Financing**

18. Export Credit Refinancing
19. Buyer Credit Guarantee

4. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Governments of the respective subject countries or other regional or local governments of such respective countries, including public bodies and confer benefit on the recipient (s). They are also alleged to be limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions and therefore specific and countervailable. They are also in some cases alleged to be contingent upon the use of domestic over imported goods and/or contingent upon export performance.

5. The producers/exporters are advised to provide information with respect to any other subsidy scheme that may have been availed by them. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of investigation.

#### **Allegation of Injury and Casual Link**

6. The petitioner has furnished information on various parameters relating to 'injury' to the domestic industry as prescribed under the Rules. The evidence provided by the petitioner's prima facie shows material injury to the domestic industry has been caused by the alleged subsidized imports from the subject country.

#### **Initiation of the Investigation**

7. The Authority finds that there is prima facie evidence of existence of countervailable subsidies on production and export of the subject goods in the subject countries and such subsidized imports causing material injury and further threat of material injury to the domestic industry through their volume and price effects.

8. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and consequent material injury and threat of injury to the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **Domestic Industry**

9. The Application has been filed by M/s Gujarat Borosil Limited, as domestic industry of the product under consideration. According to the Petitioner, they are the sole producers of the subject goods in India. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration by the petitioner or any of its related party from the subject country. Since the petitioner account for entire (100%) production of the product under consideration in India, the petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

#### **Product under consideration**

10. The product under consideration in the present application is "Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "Product under Consideration"). The minimum level of transmission required in the subject good can be achieved by keeping the iron content low, typically less than 200 ppm. The transmission level goes up by about 2%-3% when coated with an anti-reflective coating liquid. The glass whether coated or uncoated is tempered / toughened in a tempering furnace, as it is essential for solar applications. The product in the market parlance is also known by various names such as Solar Glass, Low Iron Solar Glass, High Transmission Photovoltaic Glass, Tempered Low Iron Patterned Solar Glass etc.

11. The subject good is used as a component in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications. The glass of thickness 3.2 mm and 4 mm is generally used in Solar Photovoltaic Panels and Solar Thermal applications as per the current trend. The subject goods are classified under chapter heading 70071900. However, it has been claimed by the petitioner that the subject goods are also being imported under various other tariff headings like 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900 etc. It is clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

12. The Product under Consideration is defined as follows:

“Textured Toughened (Tempered) Glass with a minimum of 90.5% transmission having thickness not exceeding 4.2 mm (including tolerance of 0.2 mm) and where at least one dimension exceeds 1500 mm, whether coated or uncoated”.

### **Like Article**

13. The petitioner has submitted that subject goods produced by the petitioner company and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the petitioner. Textured Toughened (Tempered) Glass produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

### **Country involved**

14. The present investigation is in respect of alleged subsidization of the product under consideration in Malaysia.

### **Period of Investigation (POI)**

15. The period of investigation for the purpose of present investigation is from April 2018 to March 2019 (12 months). However, the injury investigation period will cover the data of previous three years, i.e., April 2015 to March 2016, April 2016 to March-2017, April 2017 to March 2018 and POI.

### **Submission of Information**

16. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Director General  
Directorate General of Trade Remedies  
Department of Commerce, Jeevan Tara Building, 4th Floor  
5, Parliament Street  
New Delhi -110001**

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

### **Time Limit**

18. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry’s application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.



**Submission of information on confidential basis**

20. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof.

21. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

22. The confidential version shall contain all information, which is by nature confidential and/or other information, which the supplier of such information claims, as confidential. The information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

26. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

27. In terms of Rule 7(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the information or evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority